



राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद

सर्वाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय नम्बर 0141-2744283, फैक्स नम्बर 0141-2740568, ईमेल अर्डर- rsscjaipur@gmail.com



निविदा/बोली सूचना संख्या ८१/२०२५-२६

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 500 Professional Service points (Part Time Coaches for Sports Coaching and Training) हेतु ऑनलाइन निविदा/बोली आमंत्रित की जाती है। निविदा विभागीय वेबसाईट <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> व www.rssc.in पर भी उपलब्ध है।

कैटेगरी	संपूर्ण सेवा पॉइंट की लागत (रुपये में)	ईएमडी (रुपये में)	दस्तावेज शुल्क	निविदा/बोली प्रक्रिया फीस
500 Professional Service points (Part Time Coaches for sports coaching and training)	10,00,00,000	20,00,000/-	5,000	2500

सचिव
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद,
जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref No.:
20230080
eSign 1.0



Digital signature by Neetu Baruah
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved



राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद

सर्वाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय क्रमांक 0141-2744283, फैक्स क्रमांक 0141-2740568, ईमेल आईडी- rsscjaipur@gmail.com



बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में **500 Professional Service points (Part Time Coaches for Sports Coaching and Training)** हेतु मानव संसाधन से संबंधित सेवाओं के लिये पात्रता रखने वाली फर्मों/कंपनियों से ऑनलाईन (तकनीकी एवं वित्तीय) बिड आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किया जावे :-

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1	सेवा का नाम	500 Professional Service points (Part Time Coaches for Sports Coaching and Training)
2	उपापन/निविदा की पद्धति	खुली प्रतियोगी बोली
3	अनुमानित राशि	रुपये 1000.00 लाख
4	निविदा शुल्क (Bid Document Fees)	5000/- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी प्रस्तुत करनी होगी।
5	प्रक्रिया शुल्क (Processing Fees)	2500/- MD, RISL, Jaipur के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी प्रस्तुत करनी होगी।
6	अमानत राशि (EMD Fees)	20,00,000/- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी
7	बोली के प्रस्ताव शुरू करने दिनांक, समय	दिनांक <u>6.2.26</u> सायं 5.00 बजे से
8	बोली के प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम दिनांक, समय	दिनांक <u>16.2.26</u> दोपहर 1.00 बजे तक
9	डी0डी0/बैंकर्स चैक जमा करवाने की अंतिम दिनांक, समय	दिनांक <u>16.2.26</u> दोपहर 3.00 बजे तक
10	तकनीकी बोली को खोलने की दिनांक, समय	दिनांक <u>17/2/26</u> दोपहर 12.00 बजे
11	बिड डाक्यूमेन्ट, शुद्धिपत्र प्राप्त करने अथवा डाउनलोड करने की वेबसाइट	वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in , http://eproc.rajasthan.gov.in व www.rssc.in
12	अनुबंध अवधि	1 वर्ष।
13	बिड वैधता	180 दिवस।
14	कार्य सम्पादन प्रतिभूति	प्रदाय आदेश की राशि का 5 प्रतिशत।

Signature valid

(नीत बरुपाल)
Digitally signed by Neetu Barupal
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

General Instruction for Filling of Bid

1. The complete bidding document has been published on the website www.rssc.in rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in & <http://eproc.rajasthan.gov.in>, for the purpose of downloading.
2. Bidders who wish to participate in this bidding process must register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC.
4. A Two-stage selection procedure shall be adopted.
5. Bidder (authorized signatory) shall submit their offer on-line in electronic formats both for Technical and financial proposal on eProc website <http://eproc.rajasthan.gov.in>. However, DD for Tender/Bid Document Fees, EMD/Declaration payable in favor of SECRETARY, RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR, payable at Jaipur and Processing Fees payable in favor of Managing Director, RAJCOMP Info Services Limited, payable at JAIPUR. Tender/Bid Document fee, EMD/Declaration and processing fee DD Should be submitted physically at the office of RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, Jaipur and Scanned copy of same should also be uploaded along with the technical bid/ cover.
6. RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload on eProc website <http://eproc.rajasthan.gov.in>. the complete bid well advance in time so as to avoid Last hour rush issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
7. No contractual obligation whatsoever shall arise from the RFP/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the tendering authority and the successful Bidder.
8. Training for the bidder on the usage of e-Tendering system (e-Procurement) is also being arranged by RISL on regular basis. Bidder interested for training may contact e-Procurement Cell RISL for booking the Training slot.
 - a) Contact No. 0141-4022688/Helpline Help Desk Number 0120-4200462.
 - b) E-mail: eproc@rajasthan.gov.in

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की 500 Professional Service points (Part Time Coaches for Sports Coaching and Training) लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:—

1. निविदा की दर (बोली) कार्यालय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा जारी ऑनलाईन प्रपत्रों में ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रुपये 5000/- रुपये मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व निर्धारित अवधि तक ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
3. प्रोसेसिंग फीस राशि रुपये 2500/- रुपये मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व निर्धारित अवधि तक ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो MD, RISL, Jaipur के पक्ष में देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
4. अमानत (EMD Fees) की राशि रुपये 20,00,000/- रुपये मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व निर्धारित अवधि तक ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी।
5. बोली दो बिड सिस्टम में आमन्त्रित की जायेगी, जो ऑनलाईन ही संवेदक द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। **प्रथम तकनीकी बोली एवं द्वितीय वित्तीय बोली** जो कि अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी।
6. तकनीकी प्रस्तावों में सफल बोलीदाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेंगे जो निविदादाता तकनीकी बिड में सफल नहीं पाये गये उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।
7. निविदा में नियमानुसार एमएसएमई के प्रावधान लागू होंगे।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए वित्तीय बिड में बोली की दर (प्रतिशत) में प्रति माह प्रति व्यक्ति के लिए (For Per Month) अंकित की जानी है। सर्विस चार्ज 2 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
9. बजट घोषणा वर्ष 2025–26 के क्रम में 200 अल्पकालीन प्रशिक्षकों हेतु राशि रु0 4.00 करोड़ का प्रस्ताव वित्त विभाग में प्रेषित किया है जिसकी सहमति प्राप्त होने पर उक्त प्रशिक्षकों की संख्या 500 से बढ़कर 700 तथा अनुमानित बजट 10 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो जायेगा।
10. यदि इस प्रकार की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी राजकीय शुल्क, स्थानीय कर या व्यय आदि लागू होते हैं तो उसका भुगतान निविदादाता को अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा। बोलीदाता द्वारा उपरोक्त प्रकार के समर्त व्ययों को सम्मिलित करते हुये ही बोली की दर इस कार्यालय की बोली में प्रस्तुत की जानी है। किसी भी प्रकार के व्ययों के लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. **जिस निविदादाता की न्यूनतम मासिक दरें सक्षम स्तर पर अनुमोदित की जायेगी उस निविदादाता को कुल बोली राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के तौर पर कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर जमा कराकर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा।**
12. तकनीकी बोली के साथ बोलीदाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होंगे (जिसके आधार पर तकनीकी बिड का मूल्याकांन किया जायेगा) :—
 - i. बोली में अंकित पते के प्रमाण हेतु पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाइल के बिल, पेन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई एक की प्रमाणित छाया प्रतियां।
 - ii. बोलीदाता/फर्म का विगत 5 वित्तीय वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से किन्हीं 3 वित्तीय वर्षों में समान कार्य (मैनपावर/अल्पकालीन प्रशिक्षक आउटसोर्स) का औसत टर्न ओवर 1000.00 लाख से कम नहीं होना चाहिये। इस हेतु बोलीदाता को टर्न ओवर के संबंध में उक्त वर्षों के चार्टेट एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र मय यूडीआई नं0 के हस्ताक्षर मय सील के प्रति संलग्न करनी होती है।
 - iii. बोलीदाता/फर्म को चैक लिस्ट में अंकित विवरण अनुसार विगत 5 वित्तीय वर्षों (2020–21 से 2024–25) में राजकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में समान प्रकृति

RajKaj Ref No.:
20230080

eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Neetu Barupal
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

आउटसोर्स) के किये गये कार्यों के कार्य आदेश एवं कार्य संतोषजनक के अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। कार्यादेश हेतु विगत पांच वर्षों में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 800 लाख का एकल कार्यादेश या 400 लाख के दो कार्यादेश या 300 लाख के तीन एवं 200–200 लाख के 4 कार्यादेश होने चाहिए।

- iv. बोलीदाता के विरुद्ध किसी भी राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम आदि का कोई आपराधिक मामला पुलिस में दर्ज न होने तथा न्यायालय में तत्सम्बन्धी कोई वाद विचाराधीन नहीं होना चाहिए। यदि आपराधिक पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर बोली निरस्त की जा सकती है।
- v. बोलीदाता द्वारा मूल बोली प्रपत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता द्वारा पूर्ण बोली प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। प्रत्येक कॉट-छॉट पर अपने हस्ताक्षर करने होगे अन्यथा कॉट-छॉट मान्य नहीं होगी। अपूर्ण रूप से भरी हुई बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
- vi. बोलीदाता को श्रम विभाग या सक्षम स्तर पर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- vii. बोलीदाता को माल एवं सेवाकर (GST) के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
- viii. अमानत राशि, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रपत्र शुल्क का डी.डी. संलग्न करना होगा।
- ix. बोलीदाता का पेन नम्बर एवं उसकी छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

13. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के कार्य की अवधि एक वर्ष होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि से पूर्व यदि फर्म अनुबन्ध समाप्त करती हैं तो कार्यालय को तीन माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में तीन माह की अनुबन्ध राशि परिषद के खाते में जमा करानी होगी। इसके साथ ही यदि बोली की शर्तों का उल्लंघन करने, कार्य असंतोषप्रद/उचित व्यवस्था नहीं होने आदि पर उक्त समयावधि से पूर्व भी अनुबन्ध समाप्त करने का राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।

14. बोली सम्पूर्ण रूप से भरी हुई होनी चाहिए तथा चाही गई समस्त सूचना का उल्लेख होना चाहिए। बोलीदाता को बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने अनिवार्य होगे। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरी हुई बोली अथवा सशर्त बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

15. बोलीदाता को बोली अमानत राशि के रूप में निविदा जारी राशि की 2 प्रतिशत राशि का डी.डी./बैकर चैक जो सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में देय हो, बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के बाद अपनी बोली को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

17. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के सात दिवस के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जो कुल बोली राशि के 5 प्रतिशत होगी, जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प ऐपर पर अनुबन्ध करना होगा।

18. फर्म को अल्पकालीन प्रशिक्षकों की सूची, पासपोर्ट साईज फोटो सहित पहचान पत्र अनुबन्ध के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा उन पर होने वाला समस्त व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।

19. असफल बोलीदाताओं की अमानत राशि सफल बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध पत्र एवं समस्त राशि प्रस्तुत/जमा करने के बाद लौटा दी जावेगी।

20. प्रत्येक अल्पकालीन प्रशिक्षक को प्रत्येक कार्य दिवस में सामान्यतः निर्धारित समय के लिये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा तय किये गये समयानुसार प्राधिकृत अधिकारी/अनुभाग में अपनी उपस्थिति देनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन प्रशिक्षक को निर्धारित कार्यालय समय से पूर्व बुलाया जा सकता है अथवा निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात भी रोका जा सकता है।

21. सेवा प्रदाता को भुगतान संबंधित सक्षम अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर एवं प्रस्तुत नियमानुसार उपस्थिति अनुसार किया जावेगा।

22. संवेदक द्वारा नियोजित अल्पकालीन प्रशिक्षक को मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित अल्पकालीन प्रशिक्षकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

23. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों के बिल राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को संबंधित इकाई प्रभारी द्वारा उपरिथित प्रमाणित करवाने के बाद ही प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। जिससे संवेदक के व्यक्तियों को समय पर (माह की 10 तारीख तक) मानदेय का भुगतान किया जा सके।

24. ऑनलाईन प्रोसेस में यदि किसी फर्म/संवेदक द्वारा '2.00 प्रतिशत से कम सर्विस चार्ज राशि भरी जाती है तो उस फर्म की निविदा निरस्तन करने योग्य होगी। सर्विस चार्ज की राशि दो दशमलव (0.00) तक ही भरी जानी है। उदाहरण के लिए दशमलव के बाद दो अंकों में ही दरे भरी जानी होगी।

25. न्यूनतम रहे संवेदक द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में उपलब्ध करवाये जाने वाले अल्पकालीन प्रशिक्षकों की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके उपरान्त यदि परिषद में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद/सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त हुये प्रशिक्षक लगाये जाने की आवश्यकता होती है तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पार्ट टाइम कोच को लगाये जाने का सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पास नियत होगा।

26. संवेदक द्वारा नियोजित अल्पकालीन प्रशिक्षक का आचरण एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिए और संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अनुशासित रहकर अपनी ड्यूटी पूर्ण करें। यदि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा किसी अल्पकालीन प्रशिक्षक की शिकायत की जाती है तो संवेदक को उसे तुरन्त प्रभाव से बदलना होगा। संवेदक के किसी अल्पकालीन प्रशिक्षक द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है या संवेदक का कोई कर्मचारी अमानत में ख्यानत करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी और उसे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को हुये नुकसान की भरपाई करनी होगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय अल्पकालीन प्रशिक्षक की उपरिथित/रिकार्ड का आकस्मिक निरीक्षण कर सके और उसमें आवश्यक बदलाव के दिशा-निर्देश दे सके। यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान निर्धारित संख्या से कम अल्पकालीन प्रशिक्षक पाये गये तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संवेदक पर शास्ति आरोपित की जाकर संवेदक के बिल में से कटौती की जावेगी।

27. कार्यरत कोई भी अल्पकालीन प्रशिक्षक यदि किसी भी कारणवश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपरिथित देने में असमर्थ रहे तो संवेदक को उसके बिल में से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा और संवेदक को अनुपरिथित अल्पकालीन प्रशिक्षकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। संवेदक द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने पर निर्धारित दर से शास्ति आरोपित की जावेगी।

28. सफल बोलीदाता द्वारा निविदा का संचालन स्वयं को करना होगा। वह इसका उप ठेका अन्य किसी संस्था/व्यक्ति को नहीं दे सकेगा। यदि ठेके की अवधि में बोलीदाता द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षक के कार्य का उप ठेका किसी अन्य को देना पाया गया तो ठेका निरस्त कर जमा ठेका राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

29. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर एवं उनकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति अचानक/कभी भी यह जॉच कर सकेगा कि ठेके के लिये निर्धारित शर्तों की पालना सफल बोलीदाता द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। यदि किसी भी शर्त की अवहेलना पाई जाती है तो यह अवधि भंग करना सक्ता जावेगा, जिसके लिये बोलीदाता के विरुद्ध शास्ति आरोपित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धक का होगा, जिसे बोलीदाता को मानना होगा।

30. माल एवं सेवा कर (GST) की राशि सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार स्वयं के स्तर से जमा करानी होगी। माल एवं सेवा कर (GST) राशि का भुगतान परिषद द्वारा नियमानुसार किया जावेगा। माल एवं सेवा कर की राशि समय पर एवं नियमानुसार जमा नहीं कराने की स्थिति में सफल बोलीदाता संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

31. बोलीदाता द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षक कार्य का निर्धारित अवधि से पूर्व जोड़ने अथवा नियमानुसार नहीं करने के फलस्वरूप ठेका कार्य निरस्त होने, उक्त दोनों स्थितियों में ही राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा बोलीदाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य करवाया जावेगा एवं इस संबंध में किसी भी आर्थिक क्षति की पूर्ति बोलीदाता की परिषद में किसी भी प्रकार की जमा राशि से कर ली जायेगी।

32. बोलीदाता द्वारा निर्धारित धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ ही तकनीकी बोली में उपरोक्तानुसार वर्णित सूचनाएं/दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिनके आधार पर प्रस्तुत तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जायेगा एवं तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

33. बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त वर्णित शर्तों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिये तथा सूचना में वर्णित शर्तों के बारे में कोई शंका होने की स्थिति में कार्यालय से उस संबंध में वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये। इस बारे में सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा की गई व्याख्या एवं इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

34. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 30.04.18 दिनांक 14.05.2018 एवं 03/2018 दिनांक 11.07.2018 में जारी निर्देशों की पालना हेतु परिपत्र में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।

35. सफल बोलीदाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में वांछित राशि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पास जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोली प्रतिभूति, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के सफलता पूर्वक समाप्ति पर तीन माह पश्चात निम्न शर्त पूरी हो जाने के उपरांत चैक से लौटा दी जायेंगी।

36. सभी वैधानिक दायित्व, आवश्यकताये मय आयकर/वस्तु एवं सेवा कर व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संवेदक द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

37. यदि संवेदक नियोजित अल्पकालीन प्रशिक्षकको संपूर्ण देय राशि से कम राशि का भुगतान करता है तो उसका अनुबन्ध रद्द डीबार/ब्लेक लिस्ट किया जा सकेगा।

38. संवेदक द्वारा नियोजित अल्पकालीन प्रशिक्षकको के मानदेय में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी।

39. संवेदक के अल्पकालीन प्रशिक्षक द्वारा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि होने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी और वह यह सुनिश्चित करेगा कि आन्दोलनकारी परिसर में प्रवेश ना करने पावे और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर की सम्पति/कर्मचारी/अधिकारी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचा पाये। संवेदक के कर्मचारियों द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर की सम्पति अथवा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई नुकसान की भरपाई संवेदक द्वारा की जावेगी।

40. यदि ठेका अवधि के एकरान नियुक्त कार्मिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार चोट लग जाती है, तो इसके लिये नियमानुसार जो भी भुगतान होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।

41. अल्पकालीन प्रशिक्षकों से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण संवेदक/एजेन्सी द्वारा अनिवार्य रूप से रखा जावेगा एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी को किसी रिकार्ड की जरूरत पड़ने पर वह आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Neelu Barupal
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

42. संवेदक द्वारा कोई भी बाल अल्पकालीन प्रशिक्षक नहीं लगाया जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

43. वर्कमैन कम्पैनसेशन एक्ट एवं अन्य एक्ट के अन्तर्गत सभी दायित्वों, हानि, क्लेम, क्षतिपूर्ति, व्यय, मांग आदि जिम्मेदारी सम्बन्धित संवेदक की होगी और किसी भी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, परिपत्र सूचना जो कि संवेदक के कार्मिकों से सम्बन्धित है, की पालना भी अनुबन्धित संवेदक द्वारा की जावेगी।

44. प्रस्तुत बोली की मान्य वैधता 180 दिवस तक होगी एवं सशर्त बोली मान्य नहीं होगी। बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित की गई दरें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिए बोली खुलने की तिथि से छः माह तक मान्य होंगी।

45. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के साथ संबंधित प्रभारियों/जिला खेल अधिकारियों से प्रमाणित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं माहवार प्रोग्रेस रिपोर्ट संलग्न करने के उपरान्त ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। मासिक बिल प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

46. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किये जाने वाले भुगतान पर किसी भी कारण से अगर देरी होती है तो संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिक के बैंक खाते में प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक हर हाल में स्वयं के स्तर से वेतन डालना सुनिश्चित करें।

47. संवेदक को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद मुख्यालय एवं सम्पूर्ण राजस्थान में उसके अधीन समस्त जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र/स्टेडियम में अल्पकालीन प्रशिक्षक उपलब्ध कराने होंगे।

48. संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों में किसी एक ही अल्पकालीन प्रशिक्षक का नाम दोहराया नहीं जावेगा।

49. अन्य शर्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, आरटीपीपी एक्ट एण्ड आरटीपीपी रूल्स के अनुसार रहेगी।

50. बोली के संबंध में प्रथम अपील अधिकारी, सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग एवं द्वितीय अपील अधिकारी, सचिव बजट (वित्त) विभाग राजस्थान, जयपुर होंगे।

51. बोली से सम्बन्धित समस्त विवादों के निपटारे हेतु न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

52. सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर को बिना कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

53. संवेदक को अपना स्थानीय कार्यालय जयपुर जिले में खोलना अनिवार्य होगा।

54. तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Neelu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

55. वित्तीय बिड खोलने के उपरांत सफल बोलीदाताओं को गत 5 वर्षों के समान कार्य के कार्यादेशों (संतोषजनक सेवा के प्रमाण—पत्र सहित) एवं औसत वार्षिक टर्नओवर के आधार पर निम्नानुसार अंकों का विभाजन करते हुये एच 1, एच 2 एवं एच 3 का निर्णय किया जावेगा:—

Turn Over	Marks (Maximum Marks 50)	Work Order	Marks (Maximum Marks 50)
Above 20 Cr.	50	Two Order 8 Cr. Or Four Order 4 Cr. Or Six Order 3 Cr.	50
From 15-20 Cr.	40	Single Order 8 Cr. Or Two Order 4 Cr. Or	40
From 10-15 Cr.	30	Three Order 3 Cr. Or Four Order 2 Cr.	30

56. अंक गणना के पश्चात यदि एक से अधिक फर्म एच 1 या एच 2 पर आती है तो उनमें कार्य का विभाजन समान होगा अन्य स्थिति में एच 1 को 45 प्रतिशत, एच 2 को 30 प्रतिशत एवं एच 3 को 25 प्रतिशत कार्य का विभाजन किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

Other Conditions

1. If at any time during performance of the Contract, the Service Provider should encounter conditions impeding timely performance of Services, the Service Provider shall promptly notify the Procurer in writing of the fact of the delay, its likely duration and its cause(s).
2. As soon as practicable after receipt of the Service Provider's notice, the Procurer shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Service Provider's time for performance with or without penalty, in which case the extension shall be ratified by the parties by amendment of the Contract.
3. The services on service point will have to be provided by the agency within 15 days of award of work order.
4. Except as provided under terms of this document, a delay by the Service Provider in the performance of its delivery obligations shall render the Service Provider liable to the imposition of Liquidated Damages in terms of this document, unless an extension of time is agreed upon the application of L.D clause in terms of this document. As per rates below

No.	Conditions	LD %
(a)	Delay upto $\frac{1}{4}$ period as prescribed period	2.5%
(b)	Delay exceeding $\frac{1}{4}$ but not exceeding $\frac{1}{2}$ of proscribed period	5%
(c)	Delay exceeding $\frac{1}{2}$ but not exceeding $\frac{3}{4}$ period of prescribed period	7.5%
(d)	Delay exceeding $\frac{3}{4}$ of prescribed period	10%

5. On unsatisfactory services the RSSC will serve a notice to the bidder giving an opportunity to improve performance within two days. A penalty amounting to rupees one thousand per service per day will impose if the work doesn't improve even after seven days from date of notice.
6. That on the expiry of the agreement as mentioned above, the agency will withdraw all its Part Time Coaches after making knowledge transfer to new service provider if required.
7. The service provider has to provide desired part time coaches as per the norms specified in **Annexure G-1** as and when required.
8. That if any amount is found payable by the bidders towards, remuneration, and statutory dues in respect of any loss to this office property, the same shall be adjusted from the security deposit of the extent of the amount so determined reserving right to recover the deficit amount through other modes of recovery including the right to terminate the agreement without notice.

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

9. Subject to terms of this document, if the Service Provider fails to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Procurer shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, deduct from the Contract Price, as penalty, a sum equivalent to Liquidated specification as prescribed point no. 4 and the maximum deduction is 10% of the contract price in addition to this, the service provider will liable to pay the additional cost of alternative arrangements thereof.
10. For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Service Provider and not involving the Service Provider's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Procurer either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes. If a Force Majeure situation arises, the Service Provider shall promptly notify the Procurer in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Procurer in writing, the Service Provider shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.
11. The Procurer may at any time terminate the Contract by giving written notice to the Service Provider, if the Service Provider becomes bankrupt or otherwise insolvent. In this event, termination will be without compensation to the Service Provider, provided that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy, which has accrued or will accrue thereafter to the Procurer.
12. The bidder should sign all pages of tender accepting the term and condition and enclosed the same along with technical bid. It is an integral part of the tender.
13. A check list of appendable document is also enclosed (**Annexure-E**) with the tender document.
14. The bidder should also sign the undertaking (Annexure-H) and the annexure A to D as required as per RTPP Rules – 2013.
15. Any clarification regarding this tender document clauses may be obtained from the Secretary RSSC during office hours till seven days prior to opening date of technical bid.
16. The authorization certificate should also attach if the tender document is signed other than the owner of the firm.
17. No any document shall entertain after schedule time and date as described in NIB by bidder itself.
18. Service provider will assure to pay remuneration to part time coaches on 1st week of every month in their bank account.
19. Service provider will not charge any charges or any amount from the salary of part time coaches.
20. Service provider firstly take approval from RSSC before hiring part time coaches.
21. RSSC has right to ask for bank statement of service provider i.e. amount transferred to the bank A/C of part time coaches anytime.
22. RSSC has the right to take services of part time coaches at sub division level in Rajasthan. The service provider will provide services accordingly.

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
 Designation : Joint Secretary To
 Government
 Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest. -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Work/supplies or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer- in-charge/consultant for the contract.

Signature valid
Digitally signed by Neeraj Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20230080

eSign 1.0

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of in response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the **First Appellate Authority** is The Principal Secretary, Department of Sports & Youth Affairs, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur-302 005
The designation and address of the Second Appellate Authority is Finance Department of Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur- 302005

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.
- (4) Appeals not to lie in certain cases:- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-
 - (a) Determination of need of procurement
 - (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
 - (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
 - (d) Cancellation of a procurement process
 - (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque or a sum of

Signature valid
Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

- i. Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis: i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Work/supply's or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

Annexure-E

S. No.	Documents to be submitted	Submitted	Not Submitted	Page No.
1.	Scanned Copies of tender document fee, EMD and processing fees			
2.	Copy of Labour license (in Rajasthan)			
3.	Copy of Registration certificate of EPF (in Rajasthan)			
4.	Copy of Registration Certificate of ESI (in Rajasthan)			
5.	Copy of GST Registration			
6.	Copy of PAN Card			
7.	Copy of Rajasthan Shop and business Act, 1958 Or Copy of Indian Partnership Act, 1932 Or Copy of Indian Company Act, 1956/2013			
8	Certificate from Chartered Accountant having UDIN for the proof of average annual turnover in any 3 years during the last 5 year (2020-21 to 2024-25) should be at least 10.00 Crore in same service (Manpower/Part time coach outsource).			
9.	Experience of having successfully completed simillar works (Manpower/Part time coach outsource) in central govt./state govt./ autonomous institutions / boards during last 5 years (2020-21 to 2024-25) should be either of the following: - (i) Four simillar completed works costing not less than the amount equal to 20% of the estimate cost. OR (ii)Three simillar completed works costing not less than the amount equal to 30% of the estimate cost. OR (iii) Two simillar completed works costing not less than the amount equal to 40% of the estimate cost. OR (iv) One simillar completed works costing not less than the amount equal to 80% of the estimate cost.			
10.	Copy of GST paid certificate for the month of December, 2025 in GSTR-3B proforma			
11.	Bidder should enclose police verification certificate which shall not be older than 6 months.			
12.	Annexure A to D duly signed in context to RTPP Rules – 2013.			
13.	Tender document and Technical Bid and undertaking all three duly signed			
14.	Agency profile			
15.	Authorization certificate If the tender is signed other than owners			
16.	An affidavit on non-judicial stamp of Rs 100/-, not being a defaulter in EPF and not having any dispute in 7A notice and not being a defaulter in depositing ESI and GST, will have to be submitted after getting it certified by a notary.			
17.	An affidavit on non-judicial stamp of Rs 100/-, that you are not blacklisted/debarred in any department, will have to be submitted after getting it certified by a notary.			

Signature valid

Signature of Bidder Seal of Establishment
 Digitally signed by Neetu Barupal
 Full Name of Bidder with address and Date
 Designation: Joint Secretary To
 Government
 Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20230080

eSign 1.0

Annexure- F

Declaration

I/We have thoroughly read and understood the terms and conditions of the bid for providing training services to sportspersons. The bidder should never have been blacklisted or debarred by any Central Government department, State Government department, Public Sector Undertaking in India. Subject to these terms and conditions, I/We agree and undertake to provide training services to sportspersons. In case of any breach of any of the terms, conditions or orders of the bid by me/us, the competent authority shall be authorized to take action against me/us for breach of the terms/conditions of the bid. In this regard, I will accept the decision taken by the competent / authorized officer and I / we have no objection / interference in this.

Signature of the Bidder.....
Name
Address.....
Telephone.....
Date.....

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

Annexure- G

Note: - To be submitted in a separate envelope.

Tender for providing the services on job basis to RSSC

FINANCIAL BID/BOQ

Tender No.:

1. I/We accept all the terms and conditions of your Tender Notice referred to above. It is certified that the above quoted rate is in compliance with Minimum Wages Act and all the statutory provisions and rules as applicable.
2. GST as applicable paid excluding the Consolidated Service Charge.
3. Minimum Service Charge should not be less than 2% (two %).

S.No.	Particulars	Consolidated Service Charge (Rate in %)	
		In Figure	In Words
1	2	3	4
1.	Professional Service Points as per Annexure G-1, G-1(A)		

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20230080

eSign 1.0

Annexure G-1

S. No.	Name of Service	Eligibility	Remuneration (per month)	No. of Service Point (Approx)
1	Part Time Sport Coaches various districts of Rajasthan	May be International Player Or Post Graduation Diploma in Sports Coaching from NIS/ or National recognized University (6-week course will not be included) Or Senior National Medalist/ All India Inter-University Medalist Or Senior National participation/ All India Inter-University participation	International 25,000/- Or Post Graduation Diploma in Sports Coaching from NIS/ or National recognized University (6-week course will not be included) 20,000/- Or Senior National Medalist/ All India Inter-University Medalist 15,000/- Or Senior National participation/ All India Inter-University participation 13,500/-	500

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
 Designation : Joint Secretary To Government
 Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
 20230080

eSign 1.0

Annexure G-1 A

ToR for Part Time Coaches

- Provide Coaching for specific Sports to the players
- Enhancement of sporting skills in the players.
- Timing for coaching will be as under: -

Session	Summer	Winnter
Morning	6:00AM – 9.00 AM	7:00 AM – 10.00 AM
Evening	4:00PM – 7.00 PM	3:30 PM – 6:30 PM

- Participation in workshops, seminars, meeting in and outside the State.
- Any other work related to skill development assigned by District Sports Officer, RSSC.

Coordination/Reporting

- Interaction with District Sports Officer, RSSC for advice and reporting on day-to-day basis.
- Working under overall supervision and guidance of Headquarter RSSC & District Sports Officer of their respective district.
- Schedule for whole month (Including holidays).

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

Annexure-H

UNDERTAKING BY THE BIDDER

This is to certify that I/we before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them. I/We have signed all the pages in acceptance of the terms and conditions.

I/We also undertake that I/We will not adopt any malpractices at any stage of bidding/execution.

Signature of the Bidder with Seal

Name:

Designation:

Address:

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

I / We accept all the conditions (general and special conditions) mentioned in the tender notice number dated issued by the Secretary, Rajasthan State Sports Council, Jaipur. If there is any falsehood in any document and if any concealment is found then my tender should be prima facie cancelled and necessary action should be taken, which will be acceptable to me.

Signature of the Bidder with Seal

Name:

Designation:

Address:

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0

ANNEXURE-I

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,

{Tendering Authority},

_____,

_____,

I/ We {Name/ Designation} hereby declare/ certify that {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with Tender **with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR.**

He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: - Verified Signature:

Authorized Signatory: - Seal of the Organization: -

Date:

Place:

Signature valid

Digitally signed by Neetu Barupal
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2026.02.05 13:37:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

20230080

eSign 1.0